# ई-संदेश

17 जुलाई, 2025 | अंक 162

## सात दिन – सात पृष्ठ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से
16 जुलाई, 2025 को यू०एन०डी०पी० की भारत प्रमुख एवं
रेजिडेण्ट रिप्रेजेण्टेटिव डॉ० एंजेला लुसीगी
ने शिष्टाचार भेंट की।

> भारत में कृषि और पशुपालन क्षेत्र एक दूसरे से अन्योन्याश्रित : मुख्यमंत्री

> उ0प्र0 आज भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में अग्रसर : मुख्यमंत्री

> सिख गुरुओं की महानता व समर्पण भाव भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत: मुख्यमंत्री

> के0जी0एम0यू0 संस्थान समय के अनुरूप अपने कार्यों को संपादित कर रहा है।

> जमीनी स्तर पर बदलाव का प्रमाण बन चुकी है उ0प्र0 की अर्थव्यवस्था:मुख्यमंत्री

> युवाओं को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयत्नशील : मुख्यमंत्री

> तकनीकी दक्षता, प्रशिक्षण और पूर्व तैयारी के समन्वय से आपदा के प्रभाव को कम कर सकते : मुख्यमंत्री

> एक नज़र

**नए भारत का नया उत्तर प्रदेश**

# भारत में कृषि और पशुपालन क्षेत्र एक दूसरे से अन्योन्याश्रित : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 12 जुलाई, 2025 को यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग एवं पशुधन विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'भारत में पशु नस्लों का विकास कार्यशाला' का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और समृद्धि के बिना देश में खुशहाली व समृद्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत में कृषि और पशुपालन क्षेत्र एक दूसरे से अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रखते हैं। विगत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य किये गए हैं। डबल इंजन सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरुप उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जी के विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरुप आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर पशुधन, मत्स्य पालन, डेयरी के क्षेत्र में पशुपालकों, अन्नदाता किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार मिल्क प्रोड्यूसर इकाइयों को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रही है। वर्तमान में राज्य में 05 मिल्क प्रोड्यूसर इकाइयां क्रियाशील हैं। इनमें झांसी, गोरखपुर, आगरा तथा वाराणसी आदि इकाइयां सम्मिलित हैं। प्रदेश की दुग्ध समितियां आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरन्तर आगे बढ़ रही हैं। इन दुग्ध समितियों के माध्यम से लाखों महिलाएं रोजगार प्राप्त कर रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित गो-आश्रय स्थल की कार्ययोजना को वर्ष 2018 में लागू किया गया। वर्तमान में 14 लाख से अधिक गोवंश की देखभाल सरकार की गौशालाओं के माध्यम से या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पशुपालकों द्वारा की जा रही है। प्रदेश में निराश्रित गोवंश से सम्बन्धित 03 योजनाएं संचालित हो रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से गोवंश संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। प्रथम योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार निराश्रित गो-आश्रय स्थलों के माध्यम से 12 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश की देखभाल करती है। दूसरी स्कीम सहभागिता योजना के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत किसी पशुपालक को सरकार द्वारा 04 गोवंश प्रदान किये जाते हैं। इन गोवंश की देखभाल के लिए प्रत्येक माह 1500 रुपये प्रति गोवंश प्रदान किये जाते हैं। इस योजना के तहत 01 लाख 25 हजार पशुपालकों द्वारा 02 लाख से अधिक पशुधन की देखभाल की जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तीसरी योजना के अन्तर्गत कुपोषित परिवारों को निराश्रित गो-आश्रय स्थलों से एक-एक दुधारु गाय उपलब्ध करायी गयी है। इन परिवारों को गोवंश की देखभाल के लिए प्रति गोवंश 1500 रुपये की धनराशि भी उपलब्ध करायी जाती है। अब तक 10 हजार से अधिक कुपोषित परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। प्रदेश में गो-सेवा आयोग निराश्रित गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्था ठीक रखने तथा गोवंश की नस्ल सुधारने के अभियान को आगे बढ़ा रहा है। गो-सेवा आयोग को पशुपालकों व अन्नदाता किसानों को प्रशिक्षित करने की भी जिम्मेदारी सांपी गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टीसाइड के अत्यधिक प्रयोग से कैंसर, किडनी खराब होने जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टीसाइड के अत्यधिक प्रयोग के दुष्परिणाम हम सबके समक्ष दिख रहे हैं। यह केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टीसाइड बरसात में बहकर नदियों को भी प्रदूषित करता है। यह रसायन जीव-जन्तुओं के साथ-साथ मनुष्यों के लिए भी हानिकारक होते हैं। इन चुनौतियों का सामना सबको मिलकर करना है।मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्राकृतिक जीवन जीने के लिए प्राकृतिक खेती महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक खेती गो-आधारित खेती होती है, गोवंश उसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है।

# उ0प्र0 आज भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में अग्रसर : मुख्यमंत्री

**मु**ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 12 जुलाई, 2025 को लखनऊ में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन, आर्थिक विकास एवं छवि निर्माण हेतु नियोजन विभाग के अंतर्गत नवगठित आर्थिक सलाहकार समूह ने भेंट की। मुख्यमंत्री जी ने समूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि समूह की तरफ से प्राप्त सुझाव स्वागत योग्य हैं। उत्तर प्रदेश आज भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में अग्रसर है। इसके लिए प्रदेश के सभी विभाग मिलकर तेज़ गति से कार्य कर रहे हैं। आर्थिक सलाहकार समूह से प्राप्त होने वाले सुझावों का तय समय पर क्रियान्वयन आवश्यक है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' का गठन कर चुकी है, जो शीघ्र ही कार्य करना शुरु कर देगा। इस मिशन के तहत जॉब मैपिंग कर विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रदेश के युवाओं का कौशल विकास, भाषा प्रशिक्षण और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से राज्य में स्वच्छ, टिकाऊ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण में उत्तर प्रदेश निकट भविष्य में हब बनेगा। शीघ्र ही प्रदेश में स्थापित हिंदुजा ग्रुप की यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन शुरु कर देगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में आज किसानों को 15-16 घंटे बिजली मिल रही है। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को पी0एम0 कुसुम योजना के अंतर्गत 01 लाख सोलर पैनल उपलब्ध करा रही है। सरकार ने नलकूपों के सोलराइजेशन (सौर ऊर्जा से संचालन) को मिशन मोड में लागू किया है। उत्तर प्रदेश निजी पंप सोलराइजेशन में देश में अग्रणी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश का प्रदर्शन अच्छा है। विगत मई माह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कानपुर से लगभग 08 हजार मेगावाट के पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में भी उत्तर प्रदेश ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके माध्यम से वर्ष 2027 तक प्रदेश 22 हजार मेगावॉट बिजली का उत्पादन शुरु कर देगा।उत्तर प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में देश का रोल मॉडल बनेगा और सरकार की नीतियां प्रदेश को हरित ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाएंगी। विगत 08 वर्षों में प्रदेश के किसानों के हित में बहुत सारे कार्य किए गए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले प्रदेश में हर साल मात्र 500 फैक्ट्रियों का रजिस्ट्रेशन होता था।

प्रदेश सरकार ने इसके लिए अभियान चलाया, जिसके सकारात्मक परिणाम सबके सामने हैं। अब लगभग 04 हजार फैक्ट्रियों का रजिस्ट्रेशन प्रति वर्ष हो रहा है। गोवंश संरक्षण में प्रदेश ने काफी प्रगति की है।

उत्तर प्रदेश मत्स्य उत्पादन में देश में अग्रणी राज्यों में है। राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ निवेश का हब बन रहा है। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य आमजन की आय बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और प्रदेश के हर वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

# सिख गुरुओं की महानता व समर्पण भाव भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 12 जुलाई, 2025 को यहां अपने सरकारी आवास पर साहिब श्री गुरु तेगबहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित श्री गुरु तेगबहादुर सन्देश यात्रा को पुष्प वर्षा कर रवाना किया। यह यात्रा श्री गुरु सिंह सभा, नाका हिण्डोला, लखनऊ से गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब, चांदनी चौक, दिल्ली तक होगी। इसके पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने शीश पर श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी के पावन स्वरुप को धारण कर आगमन एवं स्वागत करते हुए आसन पर विराजमान किया। मुख्यमंत्री जी ने श्री गुरु ग्रन्थ साहिब के समक्ष मत्था टेका। इस अवसर पर आयोजित शबद-कीर्तन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी सम्मिलित हुए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुरु तेगबहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक जाने वाली सन्देश यात्रा बलिदान की स्मृतियों को जीवन्त बनाए रखने व वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।यह सन्देश यात्रा लखनऊ से प्रस्थान कर दिल्ली के उस स्थान तक जा रही है, जहां सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी। इस यात्रा के माध्यम से साढ़े तीन सौ वर्षों के सम्पूर्ण इतिहास को जीवन्तता प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि औरंगजेब द्वारा सनातन धर्म पर किए गए हमलों तथा अत्याचारों की खबरें उस कालखण्ड में आती थी। उस समय भय और प्रलोभन से गुरु तेगबहादुर जी महाराज को इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन वे अपने पथ से विचलित नहीं हुए। अन्ततः वे शहादत देकर भावी पीढ़ियां के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। यही शहादत की परम्परा है, जिस पर वर्तमान भारत की नींव खड़ी है।

उनके चार साहबजादों ने देश और धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान दिया था। सत्य को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सत्य हर काल व परिस्थिति में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। सिख गुरुओं का इतिहास भारत व विश्व के समक्ष सच्चाई को प्रस्तुत करता है। इसी इतिहास पर भारत की सुदृढ़ नींव खड़ी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुरु तेगबहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के अवसर पर आयोजित सन्देश यात्रा हमें प्रेरणा दे रही है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं से अपनी शहादत, त्याग व बलिदान दिया था, वर्तमान पीढ़ियों का यह दायित्व है कि गुरुओं की उस शहादत को जीवन्त बनाए रखने के लिए कार्य करे। धर्मांतरण व आपस में फूट डालने की कोशिश के प्रति हमें सतर्क रहना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में शबद-कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके उपरान्त वीर बाल दिवस सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसम्बर की तिथि को राष्ट्रीय स्तर पर 'वीर बाल दिवस' आयोजित करने का निर्णय लिया। इसे राष्ट्रीय स्तर का आयोजन बनाकर भावी पीढ़ियों के समक्ष इतिहास को जीवन्त बनाने का प्रयास किया गया है। सिख गुरुओं की महानता व समर्पण भाव सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। यह सन्देश यात्रा एक शुरुआत है, जो कोटि-कोटि भारतीयों के लिए प्रेरणा का केन्द्र रहेगी।

# के0जी0एम0यू0 संस्थान समय के अनुरूप अपने कार्यों को संपादित कर रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 14 जुलाई, 2025 को यहां किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (के0जी0एम0यू0) में लगभग 01 हजार करोड़ रुपये लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।उन्होंने सेण्टर फॉर ऑर्थोपैडिक सुपर स्पेशियलिटी, न्यू कॉर्डियोलॉजी विंग तथा न्यू गेस्ट हाउस के ऊपर अतिरिक्त तल के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया तथा जनरल सर्जरी विभाग के नवीन भवन, 500 बेड की क्षमता के ट्रॉमा सेण्टर विस्तार एवं पेशेन्ट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स, नवीन प्रशासनिक भवन तथा डायग्नोस्टिक सेण्टर एवं पेशेन्ट रिलेटिव एक्मोडेशन फैसिलिटी ब्लॉक का शिलान्यास किया। लोकार्पित भवनों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहाँ भर्ती मरीजों की कुशलक्षेम पूछी और सुविधाओं का जायजा लिया।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि के0जी0एम0यू0 प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में से एक है। आज के0जी0एम0यू0 को लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत की विभिन्न सुविधाओं की सौगात प्राप्त हुई है। लोकमंगल की कामना के लिए स्थापित के0 जी0एम0यू0 संस्थान समय के अनुरुप अपने कार्यों को सम्पादित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि के0जी0एम0यू0 ने अपने 120 वर्ष की शानदार यात्रा में अनेक मील के पत्थर खड़े किये हैं। के0जी0एम0यू0 में पूरे प्रदेश, अगल-बगल के राज्यों व नेपाल राष्ट्र से भी बहुत सारे मरीज इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि मरीजों व उनके परिजन को के0जी0 एम0यू0 के ऊपर विश्वास है कि वह वहां से स्वस्थ होकर वापस जाएंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद बलरामपुर में के0जी0एम0यू0 का एक सैटेलाइट सेण्टर स्थापित किया गया है। अब समय आ गया है कि के0जी0एम0यू0 महानगरीय सुविधा से बाहर के क्षेत्रों में अपनी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए। गत वर्ष के0जी0एम0यू0 ने अपने यहां फैकल्टी मेम्बर्स की बड़े पैमाने पर नियुक्ति की है। बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज अगले सत्र से प्रारम्भ करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार आई0आई0टी0 कानपुर के साथ 'मेड टेक कार्यक्रम' को आगे बढ़ा रही है। आई0आई0टी0 कानपुर मेडिकल टेक्नोलॉजी में अपने एक नये सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि इस सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस के साथ के0जी0 एम0यू0 और एस0जी0पी0जी0आई0 भी जुड़ें।

आज दुनिया में मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवान्स स्टेज में आ चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें मेडिकल टेक्नोलॉजी की दिशा में प्रो-एक्टिव होकर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों में लोगों ने बदलते भारत को देखा है। नये भारत ने जीवन के हर क्षेत्र में एक नयी प्रगति की है। भारत की प्रगति पूरी दुनिया में सराही जा रही है। डबल इंजन सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की उन्नति की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। एम्स जैसे संस्थान देश में स्वास्थ्य के बेहतरीन केन्द्र माने जाते हैं। आजादी के बाद से वर्ष 1998-99 तक देश में केवल एक एम्स स्थापित हुआ था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय देश में 06 नये एम्स स्थापित हुए, जिनकी संख्या विगत 11 वर्षों में बढ़कर 23 हो गयी है। एम्स केवल उच्च चिकित्सा शिक्षा के ही केन्द्र नहीं हैं, बल्कि शोध और विकास के भी वाहक हैं। के0जी0 एम0यू0 भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

# जमीनी स्तर पर बदलाव का प्रमाण बन चुकी है उ0प्र0 की अर्थव्यवस्था:मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 14 जुलाई, 2025 को यहां लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति, विकास संरचना और राजस्व स्रोतों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने राज्य की आर्थिक यात्रा को 'सम्भावनाओं से परिणाम तक' की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि यह रुपांतरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना से प्रेरित है।

मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर विशेष बल दिया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब केवल आँकड़ों की प्रगति नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर बदलाव का प्रमाण बन चुकी है।

बैठक में प्रस्तुत विवरण के अनुसार, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) वर्ष 2024-25 में 29.6 लाख करोड़ रुपये के आँकड़ें तक पहुँचने का अनुमान है, जो वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसी अवधि में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रदेश की हिस्सेदारी 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने इसे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में ठोस उपलब्धि बतायी, साथ ही यह भी कहा कि हमें वर्ष 2026 तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर अभी से ठोस रणनीति बनानी चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य की आर्थिक संरचना में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दे रहा है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि हो रही है, जबकि कृषि आधारित हिस्सेदारी क्रमिक रुप से कम हो रही है। उन्होंने 'मेक इन यूपी' मॉडल को अगले दशक के लिए औद्योगिक रणनीति का आधार बताते हुए निर्देश दिए कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नई इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए।मुख्यमंत्री जी को कृषि क्षेत्र की समीक्षा में अवगत कराया गया कि खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2024-25 में 722 लाख मीट्रिक टन तक पहुँचने का अनुमान है, जो वर्ष 2020-21 की तुलना में 100 लाख मीट्रिक टन अधिक है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पशुपालन क्षेत्र में राज्य का दुग्ध उत्पादन देश में सर्वाधिक है। अण्डा उत्पादन में भी सुधार हुआ है। लेकिन केवल कुल उत्पादन पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रति पशु उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकता है। उन्होंने नस्ल सुधार, फीड प्रबन्धन और डेयरी व्यवसाय से जुड़े डेटा का नियमित विश्लेषण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी को विनिर्माण क्षेत्र की समीक्षा में अवगत कराया गया कि राज्य में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या वर्ष 2024-25 में 27 हजार से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जरुरत है विनिर्माण को जनपदों में समान रुप से प्रसारित किया जाए, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और राज्य को राजस्व मिले। उन्होंने ज़िला उद्योग केंद्रों की क्षमता को और मज़बूत करने की आवश्यकता बताई ताकि उद्योगों से निरंतर संवाद हो सके और नई इकाइयों का पंजीयन और सहायता तंत्र बेहतर बने।

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। एस0टी0पी0आई0 के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 46,800 करोड़ रुपये मूल्य की आई0टी0 सेवाओं का निर्यात हुआ, जो वर्ष 2021-22 की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री जी ने इसे युवाओं के लिए अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र बताया। इसी तरह पर्यटन, होटल और व्यापार जैसे सेवा क्षेत्रों में भी सकारात्मक संकेत देखे गए, विशेषकर कोविड के बाद पर्यटन क्षेत्र में आगंतुकों की संख्या में क्रमशः सुधार हुआ है।

# युवाओं को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयत्नशील : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 15 जुलाई, 2025 को यहां लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल मेला एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में युवाओं को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। कुशल युवाओं के माध्यम से हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। भारत को आत्म निर्भर और विकसित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को भी आत्म निर्भर और विकसित बनाना पड़ेगा। वर्ष 2029 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं के माध्यम से हम इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस की थीम ए0आई0 और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करना है। हमें वर्तमान की आधुनिक तकनीकों को अवश्य अपनाना चाहिए। रोबोटिक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इन्टेजीजेंस, थ्री डी प्रिंटिंग आदि क्षेत्रों में युवाओं के लिए अनेक अवसर हैं। ए0सी0, फ्रिज, सीलिंग फैन, बिजली, जल जीवन मिशन, पी0एन0जी0 पाइप लाइन, वेल्डिंग तथा प्लम्बिंग आदि क्षेत्रों में भी कुशल युवाओं की मांग है। युवाओं को इन क्षेत्रों में पारंगत होना पड़ेगा। यह सब अच्छी ट्रेनिंग से सम्भव हो सकता है। इस दिशा में किए गए प्रयास सराहनीय है। जापान सहित अनेक देशों ने उत्तर प्रदेश के स्किल युक्त युवाओं की मांग की है। अन्य देशों में रोजगार के लिए जाने वाले युवाओं को प्रदेश के आई0टी0आई0, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि संस्थाओं में सम्बन्धित देशों की भाषाओं की

ट्रेनिंग प्रदान की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कार्यों तथा मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास स्केल है, जिसे स्किल में बदलने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार 02 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन तथा टैबलेट उपलब्ध करा रही है। इस योजना से अब तक 50 लाख युवाओं

को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर 150 राजकीय आई0टी0आई0 को न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का कार्य किया है। इनके माध्यम से इण्डस्ट्री और मार्केट की मांग के अनुरूप युवाओं को ट्रेड और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का काम किया है। यह उत्तर प्रदेश के युवाओं की स्केल को स्किल में बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयास का एक उदाहरण है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में लगभग 400 सरकारी तथा 03 हजार निजी आई0टी0आई0 संचालित हैं। इन सभी आई0टी0आई0 को हब एंड स्पोक मॉडल के रुप में विकसित करना होगा। सरकारी आई0टी0आई0 में मात्र 40 रुपये फीस है तथा निजी क्षेत्रों में संचालित आई0टी0आई0 के लिए सरकार इन्सेंटिव प्रदान करती है। विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप का भी प्राविधान है।यह सभी युवाओं का जीवन बेहतर करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एम0एस0एम0ई0 विभाग के माध्यम से जो युवा अपने उद्यम व स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए सी0एम0 युवा नाम की नई योजना संचालित की गयी है। इस योजना में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त आई0टी0आई0 तथा पॉलिटेक्निक डिग्री धारकों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रदेश सरकार उन्हें 05 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण तथा मार्जिन मनी उपलब्ध करा रही है। अब तक 50 हजार से अधिक युवा इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना में व्यक्ति को केवल मूलधन वापस करना है, ब्याज सरकार के द्वारा देय होगा। मूलधन वापस करने पर 7.5 रुपये लाख तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश में स्किल्ड मैनपावर की अत्यंत आवश्यकता है। युवा जिस फील्ड/ट्रेड का चयन करें, उस ट्रेड में पारंगत होना आवश्यक है।

स्वयं को इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुरुप तकनीकी रुप से सक्षम बनाना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी-2020 के अनुसार, प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी सामान्य डिग्री प्राप्त करने के दौरान एक स्किल

डेवलपमेण्ट कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को किसी न किसी ट्रेड में ट्रेण्ड करने के लिए नियमित कक्षाएं चलाई जा रही हैं। छात्र-छात्राएं आई0टी0आई0 में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। एन0ई0पी0 विद्यार्थियों को एक साथ ड्यूअल सर्टिफिकेट प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग की योजनाओं व कार्यक्रमों से लाभान्वित यूथ आइकॉन तथा टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के प्रतिनिधि, पी0आई0ए0 एवं ट्रेनिंग पार्टनर को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जी के समक्ष व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग तथा मोतीलाल नेहरु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री जी ने 05 स्किल रथों को झण्डी दिखाकर रवाना किया।

# तकनीकी दक्षता, प्रशिक्षण और पूर्व तैयारी के समन्वय से आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में 16 जुलाई, 2025 को यहां उनके सरकारी आवास पर राज्य में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी, समन्वित, वैज्ञानिक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राहत आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू0एन0डी0पी0) के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सम्पन्न हुआ। यह समझौता प्रदेश में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रमों को लागू करने, राज्य की संस्थागत क्षमता को सशक्त बनाने और बहु स्तरीय आपदा प्रबंधन व्यवस्था को तकनीकी दृष्टिकोण पर आधारित बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत है।

इस अवसर पर यू0एन0डी0पी0 की भारत प्रमुख एवं रेजिडेंट रिप्रेजेन्टेटिव डॉ0 एंजेला लुसीगी भी उपस्थित रहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से शिष्टाचार भेंट कर उत्तर प्रदेश सरकार की आपदा प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की और यू0एन0डी0पी0 की ओर से राज्य को हर सम्भव तकनीकी सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपदा प्रबंधन वर्तमान समय की एक अनिवार्य प्रशासनिक प्राथमिकता है। तकनीकी दक्षता, प्रशिक्षण और पूर्व तैयारी के समन्वय से ही हम आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। यह साझेदारी राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता को विश्वस्तरीय बनाएगी और शासन-प्रशासन को वैज्ञानिक ढंग से निर्णय लेने में समर्थ बनाएगी। यह प्रयास उत्तर प्रदेश के आपदा न्यूनीकरण प्रयासों को नई दिशा देंगे। इससे प्रदेश में जीवन, संपत्ति और अवसंरचना की रक्षा के लिए समेकित रणनीति पर कार्य करना अधिक सुगम होगा और आपदा प्रबंधन की दिशा में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा।

इस अवसर पर यू0एन0डी0पी0 की भारत प्रमुख एवं रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ने उत्तर प्रदेश सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और तत्परता इस समझौते को धरातल पर सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यू0एन0डी0पी0 तकनीकी सहायता के साथ-साथ नीति निर्माण, योजना विकास और जमीनी कार्यान्वयन तक हर स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करेगा।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इस समझौते का उद्देश्य राज्य के विभिन्न स्तरों पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रमों की व्यापक श्रृंखला को लागू करना है, जिससे राज्य की आपदा प्रबन्धन प्रणाली अधिक समावेशी, जवाबदेह और प्रभावी बन सके।

समझौते के प्रमुख बिंदुओं में सभी 75 जनपदों में जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं और 15 विभागों की विभागीय आपदा प्रबंधन योजनाओं का विकास शामिल है। राज्य के 10 विभागों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। साथ ही, 20 प्रमुख शहरों में संभावित आपदाओं को ध्यान में रखते हुए जोखिम व संवेदनशीलता का मूल्यांकन कराया जाएगा। इन्हीं शहरों में शहरी आपदा प्रबंधन योजनाएं भी विकसित की जाएंगी।

**मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिनांक 15 जुलाई 2025 को अपने सरकारी आवास 5- कालिदास मार्ग लखनऊ पर पुष्प की खेती करने वाले किसानों से संवाद करते हुए।**

**मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 15 जुलाई, 2025 को उनके सरकारी आवास पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत हुए वर्ष 2008 एवं वर्ष 2010 बैच के प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की।**

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित